



भारत के मीडिया में जाति प्रतिनिधित्व: जनमत के साधन मीडिया में अत्यंत निराशाजनक है एससी,एसटी एवं ओबीसी वर्ग की भागीदारी

डॉ.रमेश चंद बैरवा

सह आचार्य, राजनीति विज्ञान

बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय,अलवर

विश्व प्रसिद्ध सामाजिक संस्था ऑक्सफैम इंडिया ने पिछले दिनों भारतीय मीडिया में वंचित जाति समूहों के प्रतिनिधित्व की मौजूदा स्थिति के बारे में "हू टेल्स अवर स्टोरीज मैटर्स: रिप्रेजेंटेशन ऑफ मारजेनेलाइज्ड कास्ट गुप्स इन इंडियन न्यूजरूम" नामक एक खास रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट न्यूजलॉन्डी नामक प्रसिद्ध डिजिटल मीडिया चैनल ने तैयार की है। रिपोर्ट का मकसद मीडिया में जातिगत वंचना और भेदभाव की स्थिति पर गंभीर विमर्श शुरू करना और मीडिया को समावेशी बनाना है। यह रिपोर्ट बताती है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी भारत के मीडिया में ब्राह्मण,क्षत्रिय,वैश्य जैसी उच्च जातियों का वर्चस्व कायम है। आदिवासी तबके का प्रतिनिधित्व नगण्य हैं। दलित तबके के पत्रकार भी बहुत ही कम हैं और जो भी हैं वे अक्सर सामाजिक कार्य या राजनीति से जुड़े हैं,व्यावसायिक पत्रकार नहीं के बराबर हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी कोई खास जगह नहीं मिल पाई है।

न्यूजलॉन्डी की यह रिपोर्ट भरपूर सबूतों के साथ बताती है कि दलित,आदिवासी,अन्य पिछड़ा वर्गों की पहुंच मीडिया में समुचित नहीं है,वह मीडिया जो जनमत तैयार करता है। रिपोर्ट अंग्रेजी एवं हिंदी अखबारों,जिनकी रीडरशिप ज्यादा है,में प्रकाशित खबरों तथा 7 अंग्रेजी टीवी चैनल और इतने ही हिंदी चैनलों पर होने वाले डिबेट पर केंद्रित है। रिपोर्ट बताती है कि प्रधान संपादक,प्रबंध संपादक, कार्यकारी संपादक,ब्यूरो चीफ जैसे 121 महत्वपूर्ण पदों में से 106 पर उच्च जाति के व्यक्ति हैं। दलित, आदिवासी तबके का एक भी व्यक्ति मीडिया के इन बड़े पदों पर नहीं है। खास चर्चा के 4 में से 3 एंकर उच्च जाति के हैं। कोई भी दलित,आदिवासी एवं ओबीसी से नहीं है। खास चर्चा कार्यक्रम के 70 प्रतिशत पैनलिस्ट उच्च जाति के हैं। अंग्रेजी अखबारों में मुश्किल से 5 प्रतिशत एवं हिंदी अखबारों में करीब 10 प्रतिशत लेख दलित,आदिवासियों द्वारा लिखे जाते हैं। जाति के बारे में लिखने वाले आधे से ज्यादा उच्च जाति के हैं। करीब 72 प्रतिशत लेख उच्च जाति के व्यक्तियों द्वारा लिखे जाते हैं। 12 पत्रिकाओं के कवर पेज के 972 लेखों में से मात्र 10 लेख ही जाति के बारे में पाए गए हैं।

सीएनएन न्यूज18,इंडिया टुडे, मिरर नाउ,एनडीटीवी,राज्यसभा टीवी,रिपब्लिक टीवी,टाइम्स नाउ जैसे इंग्लिश टीवी चैनल के बड़े पदों पर करीब 90 प्रतिशत उच्च जाति के व्यक्ति हैं। 75 प्रतिशत एंकर उच्च जाति के हैं। इंडिया टुडे के 65, सीएनएन न्यूज18 के 66 प्रतिशत,एनडीटीवी के 71,राज्यसभा टीवी के 89 प्रतिशत पैनलिस्ट उच्च जाति के हैं। औसतन करीब 55 प्रतिशत पैनलिस्ट उच्च जाति,6 प्रतिशत दलित,8 प्रतिशत ओबीसी के हैं। आदिवासी तबके से एक प्रतिशत पैनलिस्ट भी नहीं है। डिबेट के लिए आमंत्रित

पैनलिस्ट में शैक्षिक जगत के उच्च जाति के 52 प्रतिशत, दलित 4 प्रतिशत, ओबीसी 21 प्रतिशत हैं। राजनीतिक विश्लेषकों में 49 प्रतिशत उच्च जाति के, 7 प्रतिशत दलित, 11 प्रतिशत ओबीसी हैं। धार्मिक क्षेत्र के पैनलिस्ट में 49 प्रतिशत उच्च जाति के, 4 प्रतिशत दलित, ओबीसी 1 प्रतिशत हैं। पैनलिस्ट में सामाजिक कार्यकर्ता 52 प्रतिशत उच्च जाति के, 3 प्रतिशत दलित, एक प्रतिशत आदिवासी, 5 प्रतिशत ओबीसी हैं। थिंक टैंक के रूप में आमंत्रित पैनलिस्ट में 81 प्रतिशत उच्च जाति के हैं। पैनलिस्ट में स्वयंसेवी संस्थाओं के 50 प्रतिशत एवं पार्टी प्रवक्ताओं में 63 प्रतिशत उच्च जाति के हैं, जबकि दलित 3 प्रतिशत, ओबीसी 5 प्रतिशत तथा आदिवासी शून्य के करीब हैं। हिंदी टीवी चैनलों में से बड़े पदों पर 100 प्रतिशत उच्च जाति के हैं। एंकरों में उच्च जाति 80 प्रतिशत उच्च जाति के एवं ओबीसी के 7 प्रतिशत हैं। आज तक में 73, न्यूज़ 18 में 64, इंडिया टीवी में 76, एनडीटीवी में 65, राज्यसभा टीवी में 89, रिपब्लिक इंडिया में 74, ज़ी न्यूज़ में 70 प्रतिशत एंकर उच्च जाति के हैं।

औसतन 60 प्रतिशत पैनलिस्ट उच्च जाति, 6 प्रतिशत दलित, एक प्रतिशत से भी कम आदिवासी और 8 प्रतिशत ओबीसी के हैं। टीवी चैनल्स पर आमंत्रित राजनीतिक विश्लेषकों में 58 प्रतिशत उच्च जाति, 6 प्रतिशत दलित, 6 प्रतिशत ओबीसी के हैं। डिबेट में आमंत्रित पार्टी प्रवक्ताओं में 60 प्रतिशत उच्च जाति, 4 प्रतिशत दलित, 9 प्रतिशत ओबीसी एवं सिर्फ आधा प्रतिशत आदिवासी हैं। शिक्षा जगत से आए पैनलिस्ट में 55 प्रतिशत उच्च जाति, 4 प्रतिशत दलित, 3 प्रतिशत ओबीसी एवं सिर्फ एक प्रतिशत ही आदिवासी हैं। डिबेट में बुलाए सामाजिक कार्यकर्ताओं में से 42 प्रतिशत उच्च जाति, 7 प्रतिशत दलित, 10 प्रतिशत ओबीसी एवं सिर्फ 2 प्रतिशत आदिवासी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, इकनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ जैसे बड़े अंग्रेजी अखबारों के बड़े पदों पर 92 प्रतिशत उच्च जाति एवं 8 प्रतिशत ओबीसी तबके के हैं। दलित और आदिवासी को कोई जगह नहीं मिल पाई है। इन अखबारों में पैनलिस्ट में 53 प्रतिशत उच्च जाति, 6 प्रतिशत दलित, 8 प्रतिशत ओबीसी एवं सिर्फ एक प्रतिशत आदिवासी हैं।

जाति के मुद्दों पर लिखने वालों में टाइम्स ऑफ इंडिया के 100 प्रतिशत उच्च जाति के हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में 24 प्रतिशत उच्च जाति, 40 प्रतिशत ओबीसी, 15 प्रतिशत दलित हैं। ऐसे ही इंडियन एक्सप्रेस में 50 उच्च जाति, 20 प्रतिशत ओबीसी, टेलीग्राफ में 86 उच्च जाति एवं 20% ओबीसी हैं। औसतन देखा जाए तो इन अखबारों में लिखने वाले 51 प्रतिशत उच्च जाति, 7 प्रतिशत दलित एवं 6 प्रतिशत ओबीसी के हैं। आदिवासियों की स्थिति शून्य के बराबर है।

दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, प्रभात खबर जैसे बड़े हिंदी अखबारों के बड़े पदों पर 87 प्रतिशत उच्च जाति, 12 प्रतिशत ओबीसी तबके से हैं। दलित, आदिवासी को कोई स्थान नहीं मिल पाया है। इन अखबारों में 56 प्रतिशत पैनलिस्ट उच्च जाति, 8 प्रतिशत दलित, 10 प्रतिशत ओबीसी एवं सिर्फ एक प्रतिशत आदिवासी समुदाय से हैं। जाति के मुद्दों पर लिखने वाले अमर उजाला में 100 प्रतिशत उच्च जाति के हैं। लेखकों में दैनिक भास्कर में 44 प्रतिशत उच्च जाति, 16 प्रतिशत ओबीसी हैं एवं 10 प्रतिशत दलित हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में 23 प्रतिशत उच्च जाति, 13 प्रतिशत ओबीसी एवं 10



प्रतिशत दलित हैं। नवभारत टाइम्स के लिए लिखने वालों में 76 प्रतिशत उच्च जाति, 8 प्रतिशत दलित, 15 प्रतिशत ओबीसी हैं। राजस्थान पत्रिका के लेखकों में 90 प्रतिशत उच्च जाति एवं 10 प्रतिशत ओबीसी हैं। कुल औसतन 52 प्रतिशत लेखक उच्च जाति, 6 प्रतिशत दलित, 4 प्रतिशत आदिवासी एवं 12 प्रतिशत ओबीसी हैं।

फर्स्टपोस्ट, न्यूजलॉन्डी, स्कॉल डॉट इन, स्वराज्य, द केन, न्यूज मिनिट, द प्रिंट, द क्रिट, द वायर, न्यूजलॉन्डी हिंदी एवं सत्याग्रह जैसे डिजिटल मीडिया के वेब चैनल के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि डिजिटल मीडिया में भी बड़े पदों पर 84 प्रतिशत उच्च जाति एवं 5 प्रतिशत ओबीसी के हैं। इन चैनल पर पैनलिस्ट में 55 प्रतिशत उच्च जाति, 5 प्रतिशत दलित, 8 प्रतिशत ओबीसी तथा 1 प्रतिशत से भी कम आदिवासी हैं। इनमें जाति के मुद्दों पर लिखने वाले 56 प्रतिशत उच्च जाति, 5 प्रतिशत दलित एवं 10 प्रतिशत ओबीसी हैं। आदिवासी एक भी प्रतिशत नहीं है।

इंडिया टुडे, फ्रंटलाइन, कारवां, फेमिना, बिजनेस टुडे, आउटलुक, स्पोर्ट्स स्टार, तहलका, ऑर्गेनाइजर जैसी पत्रिकाओं के नेतृत्वकारी पदों पर 73 प्रतिशत उच्च जाति, 13 प्रतिशत ओबीसी हैं। दलित, आदिवासी का प्रतिनिधित्व नगण्य है। इनके पैनलिस्ट में 52 प्रतिशत उच्च जाति, 7 प्रतिशत दलित, 9 प्रतिशत ओबीसी तथा करीब आधा प्रतिशत ही आदिवासी हैं। डिजिटल मीडिया के इन वेब चैनल्स पर जाति के मुद्दे पर लिखने वालों में करीब 36 प्रतिशत उच्च जाति, 10 प्रतिशत दलित, 16 प्रतिशत ओबीसी हैं। आदिवासी का प्रतिनिधित्व नगण्य है।

न्यूजलॉन्डी द्वारा तैयार की गई तथा ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रकाशित यह खास रिपोर्ट एक बार फिर साबित करती है कि भारत की मीडिया आबादी के छोटे से हिस्से का ही प्रतिनिधित्व करता है। दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। आज भी उच्च जातियों का वर्चस्व है। अतः भारत को एक समावेशी, समतामूलक समाज बनाने एवं लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए यह स्थिति बदलनी चाहिए।

संदर्भ सूची:

1. ऑक्सफैम इंडिया, 2019 "हू टेल्स अवर स्टोरीज मैटर्स: रिप्रेजेंटेशन ऑफ मारजेनेलाइज्ड कास्ट गुप्स इन इंडियन न्यूज़रूम"